राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन /1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र /भोपाल /371 /18-20

वर्ष-19,अंक-12 (चौबीस सालों से प्रकाशित) | भोपाल, शनिवार 28 अप्रैल 2018 | पेज-8,मूल्य पांच रुपया

भारत को कश्मीर पर दो टूक फैसला लेना होगा-जनरल बख्शी

भोपाल,(प्रेस इंफार्मेशन सेटर))। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो लोग इस पर दावा करते हैं उन्हें खुली चुनौती है कि वे इसे लेने का प्रयास करके देख लें। भारत सरकार की सहनशील नीति के कारण ही आज तक कश्मीर अशांत है। सरकार को दो टूक फैसला लेना होगा। यदि हम सहते रहेंगे तो कश्मीर के नाम पर लोग हमारे सिर पर बैठने का प्रयास करते रहेंगे। अब समय आ गया है जब कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए सुलझा ली जाए और देश में अमन चैन स्थापित किया जाए। सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही। मध्यप्रदेश प्रेस क्लब के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक और विख्यात लेखक राजशेखर व्यास ,कंप्यूटर वैज्ञानिक चंद्रकांत राजू ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

जनरल जी डी बख्शी ने कहा कि भारत विरोधी ताकतें बरसों से देश को खंडित करने का प्रयास करती रहीं हैं। जाति और धर्म के नाम पर देश को विभाजित करके भारत की विकास यात्रा बाधित की गई है। अंग्रेजों ने पहली जातिगत जनगणना वर्ष 1872 में कराई थी। देश को आजाद कराने के लिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने देश में जातिवादी वैमनस्य के बीज बोए। आजादी के बाद संविधान के नाम पर कभी जमीनी सच्चाई बताकर जातियों की खाई खोदी जाती रही है। भारत को कमजोर बनाने वाली ताकतें यहां अपनी पकड़ नहीं खोना चाहतीं इसलिए वे तरह तरह के षड़यंत्र कभी आईएसआई कभी वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से करती रहती हैं।

जनरल बख्शी ने कहा कि भारत के करदाताओं से एकत्रित धन से चलने वाले जवाहर लाल नेहरू विवि के हर छात्र पर आठ लाख रुपया हर साल खर्च होता है। इसके बावजूद वहां अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाने वाली मानसिकता पढ़ाई जाती है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हैं। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के नारे लगाने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद भारत में ही मानवाधिकारों के नाम पर और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

कमलनाथ के सहारे ठाकुरों को नाथेगी कांग्रेस

नई दिल्ली = कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य में पार्टी की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को सौंपी गई है। साथ ही उनके अलावा चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लंबे समय से ठाकुरों के विद्रोह से हलाकान कांग्रेस ने इस बार उन्हें बेदम करने के लिए अपने थैलीशाह कमलनाथ को कमान सौंपी है।

वहीं, गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अनुशंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने पार्टी इकाई में बदलाव का आदेश जारी किया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओर से जारी विज्ञप्ति में वर्तमान अध्यक्ष अरुण यादव के स्थान पर कमलनाथ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं चार अन्य नेताओं को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्षों में बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जीतू पटवारी और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कमलनाथ ने कहा कि वह आपसी तालमेल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)और गैर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की हार सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। इसके लिए स्थानीय ताकतों से भी तालमेल बनाया जाएगा।

अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, %प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसके लिए मैं प्रतिबद्धता, साहस और आपसी तालमेल के साथ भाजपा और गैर-धर्मनिरपेक्ष ताकतों की हार सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा।

कमलनाथ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

डालमिया चमकाएगा लालकिला

नई दिल्ली(ब्यूरो)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने लाल किला स्थित मुमताज महल संग्रहालय पर ताला लगाने के बाद स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय को भी बंद कर दिया है। एएसआइ का कहना है कि ये दोनों संग्रहालय 15 अगस्त तक नए रूप में तैयार कर जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं लाल किले की कैंटीन भी बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नई कैंटीन डालमिया समूह द्वारा खोली जाएगी। जिसमें अभी समय लग सकता है। वहीं पार्कों के विकास के साथ-साथ पुराने निर्माण तोड़े जाने का कार्य जारी है।

बता दें कि अंग्रेजों के जमाने की बनी जिस इमारत में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय चल रहा था। इस इमारत का संरक्षण कार्य कराया जा रहा है। यह वही इमारत है जिसमें बंदी बनाए गए आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के मामले की सुनवाई के लिए अदालत लगी थी। यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न आयामों की याद दिलाता है। जिसमें रानी झांसी से लेकर

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

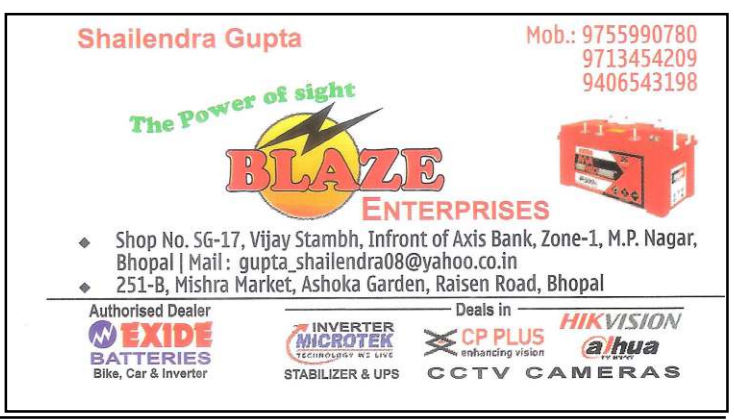

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
नायक बादशाह
भोपाल, शनिवार 28 अप्रैल 2018

लाल किले से निकला मोदी संदेश

लाल किला भारत की आजादी का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजों ने कामनवेल्थ देशों के डोमिनिक राज्य के रूप में भारत को आधी अधूरी आजादी दी थी। इसके बावजूद किला फतह करने वाली मानसिकता को पोषित करने के लिए नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को आजादी का संदेश दिया था। हिंदू मुसलमानों में फूट के बीज बोने के लिए पाकिस्तान बनाया गया और नेहरू की कांग्रेस ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान की साझा विरासत के रूप में लालकिला आज भी दोनों देशों के जिज्ञासुओं के लिए अचरज का केन्द्रबिंदु बना हुआ है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देशों से आने वाले पर्यटक भारत के स्वाधीनता संग्राम को समझने के लिए इस किले का भ्रमण जरूर करते हैं। इसके बावजूद आज ये किला गंदगी और अव्यवस्था की जीती जागती मिसाल है। यहां तैनात सरकारी अमला कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी व्यवस्था के नाम पर पर्यटकों से हुज्जत करता दिख जाता है। भारत में वैसे तो कई लाजवाब किले हैं। कई तो इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर आज के भवन भी बेनूर नजर आते हैं। इसके बावजूद लालकिला भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। यहां से प्रसारित प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश भारत की मजबूत सोच का उद्योष करता है। इसके बावजूद आजादी के बाद से इस धरोहर से गद्दारी की जाती रही है। सरकारीकरण की भेंट चढ़ चुकी इस इमारत पर वैसे तो करोड़ों रुपया खर्च होता है पर हकीकत में ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ता है। यहां टिकिटों से होने वाली कमाई भी इतनी नहीं कि लालकिले के रखरखाव पर होने वाले खर्च की भरपाई भी हो सके। इस सच्चाई को देश के शासक भी समझते हैं लेकिन उनमें इस विरासत के साथ न्याय करने का साहस भी कभी नहीं रहा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने फैसला लिया और इस इमारत का रखरखाव डालमिया समूह को सौंप दिया है। डालमिया समूह कांग्रेस के दौर से ही भारत की राजनीति का प्रमुख स्तंभ रहा है। अर्चना डालमिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में श्रीमती सोनिया गांधी की प्रमुख सहयोगी रहीं हैं। इसके बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि का भाव रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर समूह को ये जवाबदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री की आलोचना को बुद्धिमत्ता बताने वाले नाकारा और मक्कार बदमाश लोग इसे लालकिला बेच देना बता रहे हैं। मध्यप्रदेश की विधानसभा इस बात की जीती जागती मिसाल है जब इसकी साफ सफाई का ठेका निजी कंपनी को दे दिया गया तो ये इमारत जगमगाने लगी। खर्च भी घटा और नतीजे भी मिले। लाल किले के लिए जो नया करार किया गया है उससे देश की आय भी बढ़ी है और फिजूलखर्ची भी बंद हुई है। दरअसल लाल किले के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश को सीधा संदेश भी दिया है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों और खासतौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश पर जो सरकारीकरण थोपा था वक्त के साथ वह गहरी गद्दारी साबित हो रहा है। सरकारी नौकरी का असर ही इतना नशीला है कि इसमें आने वाले अफसर हों या कर्मचारी उनमें लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का भाव खुद ब खुद पनप जाता है। जो मेहनतकश ईमानदार लोग इन नौकरियों में आते हैं वे मक्कारों से इतने प्रताडित किए जाते हैं कि सेवा भाव से उनका मोह भंग हो जाता है। अच्छे काम का कोई सिला नहीं और बुरे काम की कोई सजा नहीं। इस भाव ने सरकारीकरण के कथित उद्देश्य को धूल धूसरित कर दिया है। आजादी के बाद की सरकारों ने जो माहौल दिया उसके कारण कोऊ नृप होय हमें का हानि वाला अंदाज देश के गली चौबारों में पसर गया है। वोटरों को नाराज न करने की धूर्तता में सरकारों ने कर्ज लेने की जो अंधी दौड़ शुरु की उसके चलते उत्पादकता जमीन पर आ गई है। इसके बावजूद सत्ता के दलाल ऐसा माहौल खींचने में जुट रहे कि मानों हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तरक्कीपसंद देश हो। मोदी की सख्ती इस दिशा में गेम चेंजर साबित हो रही है। लालकिले का फैसला बता रहा है कि देश में तेजी से उत्पादकता बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। विकास के नाम पर सरकारीकरण के जो सफेद हाथी पाल लिए गए थे उनसे आजादी पाना आज भारत की प्राथमिकता है। लालकिला हमारी आजादी का प्रतीक है तो यहां से निकला संदेश भी बेशकीमती है। हमें जल्दी से जल्दी भौंडे सरकारीकरण से मुक्ति पानी होगी। वो मानस बदलना होगा जो हमें पिंजरे में बंद कर देता है। संतोष की बात है कि खुले आसमान में उड़ने के लिए देश ने 1991 में मुक्त बाजार की जो व्यवस्था अपनाई थी पर उस पर अमल अब मोदी सरकार ने शुरु किया है। कहा जाता है **जो मारे सो मीर** जाहिर है मोदी सरकार बरसों बाद देश की अच्छी शासक साबित हो रही है। लालकिले की आवाज तो यही गीत सुना रही है।

कमलनाथ को बंटोरनी होगी बिखरी कांग्रेस

सक्रियता के अभाव से जूझ रही कांग्रेस में ऊर्जा भरना कमलनाथ के लिए चुनौती होगी. राज्य में शिवराज सरकार के खिलाफ माहौल तो है मगर ये माहौल कांग्रेस के पक्ष में है ऐसा कोई नहीं मानता.कांग्रेस के तमाम गुट कमलनाथ के पक्ष में खड़े होंगे इसकी संभावनाएं अभी बहुत क्षीण हैं।

ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़

नई दिल्ली- कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर आलाकमान ने बता दिया कि गांधी परिवार का भरोसा और संसदीय कार्यकाल का लंबा अनुभव रखने वाले कमलनाथ, मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेसी नेताओं पर भारी पड़े. मध्य प्रदेश के इस चुनावी साल में लंबे वक्त से पार्टी अध्यक्ष को बदलने की कवायद जारी थी. पार्टी कार्यकर्ता से लेकर निवर्तमान अध्यक्ष अरुण यादव तक भ्रमित थे कि क्या होने जा रहा है? क्यों पार्टी आलाकमान किसी नियुक्ति में इतना वक्त लगा रहा है? मध्य प्रदेश में पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए ये तय करना पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए आसान नहीं था.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हमेशा से नेताओं की भीड़ रही है. एक-दो नहीं कई नेता एमपी कांग्रेस की पहचान रहे हैं. कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यव्रत चतुर्वेदी, अजय सिंह और अरुण यादव का नाम इनमें शूमार है. लेकिन धीरे-धीरे जब ये तय हो गया कि चुनाव कमलनाथ और सिंधिया के बीच ही होना है तो ये चयन आसान नहीं था. ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां उम्र और उत्साह में सब पर भारी पड़ रहे थे तो वहीं कमलनाथ अपने संपर्क और संसाधन में किसी भी बड़े नेता के आगे दिख रहे थे.

दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा यात्रा के बाद कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाया

सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से आलाकमान को महाराजा और आम आदमी के सीएम के बीच मुकाबला होने की आशंका थी. वहीं शिवराज सिंह चौहान की युवा और मेहनती छवि के सामने कमलनाथ बुजुर्ग और पुराने जमाने के नेता ज्यादा लग रहे थे. लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा यात्रा के बाद कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाकर उनके नाम पर सहमति बनायी. आलाकमान ने अनुभवी कमलनाथ को प्राथमिकता दी. लेकिन इसके साथ ही कमलनाथ के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये भी बता दिया कि सिर्फ कमलनाथ ही आलाकमान की इकलौती पसंद नहीं है.

सिंधिया का सहयोग कमलनाथ के लिए मायने रखेगा

इंदौर के युवा नेता जीतू पटवारी, सागर के दलित चेहरे सुरेन्द्र चौधरी, ग्वालियर जिले के सक्रिय नेता रामनिवास रावत और बडवानी जिले के युवा आदिवासी चेहरे बाला बच्चन को पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. इन्हें मिलकर 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए संयुक्त प्रयास करना है. ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष का पद देकर खुश करने की कोशिश की है. सिंधिया का सहयोग कमलनाथ के लिए बहुत मायने रखेगा.

सक्रियता के अभाव से जूझ रही कांग्रेस में ऊर्जा भरना कमलनाथ के लिए चुनौती होगी. राज्य में शिवराज सरकार के खिलाफ माहौल तो है मगर ये माहौल कांग्रेस के पक्ष में है ऐसा कोई नहीं मानता. कैसे पंद्रह साल पुरानी सरकारी की एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ा जाए, ये कमलनाथ को सोचना होगा.

संजय गांधी के कहने पर पहली बार छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतरे थे कमलनाथ

कमलनाथ के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनका सियासी अनुभव है. कलकत्ता के रहने वाले कमलनाथ 1980 के चुनाव में पहली बार संजय गांधी के कहने पर छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतरे तो अबतक वहीं पर कायम हैं. एक लोकसभा चुनाव छोड़ नौ चुनाव जीतने वाले कमलनाथ ने आदिवासी जिले छिंदवाड़ा का कायाकल्प कर रखा है. वे छिंदवाडा के विकास मॉडल को आगे जाकर भुना सकते हैं. जनता को बता सकते हैं कि छिंदवाड़ा जैसा ही विकास वे पूरे प्रदेश का कर सकते हैं. उनकी बात कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ ही जनता भी सुनती है. फिलहाल दिल्ली और छिंदवाड़ा की राजनीति करते करते प्रदेश के बाकी हिस्से से वे दूर रहते हैं. संसाधनों की बहुलता भी कमलनाथ की बड़ी ताकत है. वे बड़े कारोबारी हैं. धन-धान्य की बहुलता उनके पास है.

बड़ी परेशानी कमलनाथ की 71 साल की उम्र है. चुनाव के दौरान वे कितनी भागदौड़ कर पाएंगे ये देखना होगा. उनका मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है जो सुबह से लेकर देर रात तक जनता के बीच में रहते हैं. कमलनाथ को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है. देखना ये है कि क्या कमलनाथ, राज्य में कांग्रेस के पंद्रह साल का सत्ता का सूखा दूर कर पाएंगे?

भाजपा में दलित मुख्यमंत्री के लिए गजभिए ने खोला मोर्चा

भोपाल। दलितों पर ढीली होती भाजपा की पकड़ को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. इंद्रेश गजभिए ने दलित मुख्यमंत्री की मांग शुरु कर दी है। उन्होंने भोपाल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से पार्टी पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेशक कुछ दलितों को नेता बनाया है लेकिन अब वह दलितों के असली नेताओं की मांगों को अनसुना नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर सवर्णों का कब्जा है और दलितों की उपेक्षा किए जाने से उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसका समाधान केवल दलित मुख्यमंत्री बनाकर ही किया जा सकता है।

पार्टी फोरम से बाहर दलित मुख्यमंत्री की मांग को उन्होंने दलितों की आवाज बताते हुए कहा कि वे दलितों की बेहतरी के लिए भाजपा को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में देखते हैं इसलिए वे खुलेआम ये मांग कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम को भाजपा के दलित नेताओं का समर्थन है या नहीं ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें दलितों का नेता बनाया है जबकि मैं स्वयं दलितों का नेता हूं, इसलिए दलितों की आवाज बुलंद करना मेरा दायित्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा में थावरचंद गेहलोत, डॉ.सत्यनारायण जटिया, मनोहर ऊंटवाल, गौरीशंकर शेजवार, लाल सिंह आर्य और कई अन्य दलित नेता भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद की जवाबदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें दलितों को गृहमंत्री बनाती रहीं हैं। भाजपा ने ही पहले जगदीश देवड़ा को गृहमंत्री बनाया था। जबकि कांग्रेस ने महेन्द्र बौद्ध को गृहमंत्री बनाया था। इसके विपरीत आज राज्य मंत्रिपरिषद में केवल एक दलित नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आबादी के मान से मंत्रिपरिषद में तीन कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री दलित वर्ग से लिए जाने चाहिए लेकिन मौजूदा सरकार इस परंपरा का पालन नहीं कर रही है। प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जैसे सभी पदों की कमान सवर्णों को सौंपी गई है। सभी उच्च पदों में दलितों की भागीदारी न होने से दलितों के विरुद्ध बढ़ने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति- जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.इंद्रेश गजभिए ने कहा कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े सात करोड़ आबादी में से तीन करोड़ की आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की है। अठारह प्रतिशत दलित अनुसूचित और बाईस प्रतिशत आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। प्रदेश की अस्सी फीसदी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इसके बावजूद भाजपा शासित बाईस राज्यों में एक भी अनुसूचित जाति या जनजाति के नेता को महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीन दयाल जी उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के कल्याण की बात कहते थे। पार्टी को इसी नीतिगत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सत्ता की बागडोर दलित नेता को सौंपनी चाहिए। इससे दलितों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि आज भी दलितों पर जातिवादी वैमनस्य के चलते हमले, महिलाओं से बलात्कार, नल व कुएं से पानी भरने पर रोक, घोड़ी पर बारात निकालने की मनाही, श्मशान घाट पर अंत्येष्टि पर रोक, मंदिर में प्रवेश पर निषेध जैसी घटनाएं घटित हो रहीं हैं। पिछले सालों की तुलना में दलितों के विरुद्ध सोलह प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। उन्हें रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए दलित मुख्यमंत्री बनाकर दलितों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

श्री गजभिए ने कहा कि वे जब स्वयं मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वितत एवं विकास निगम के अध्यक्ष थे तब उन्होंने प्रदेश भर में दलितों को रोजगार के लिए कर्ज बांटने के लिए मेलों का आयोजन किया था। अब न तो दलितों को कर्ज दिए जा रहे हैं और न ही उन्हें कर्जमाफी का लाभ दिया जा रहा है। चार साल पहले निगम के अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रदेश भर में दलित मेलों के माध्यम से युवाओं को सौ सौ करोड़ रुपए के ऋण बांटकर पचास हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराए थे। पिछले चार सालों से ये काम बंद है इसलिए दलितों में आक्रोश व्याप्त है।

भाजपा में दलित मुख्यमंत्री के लिए गजभिए ने खोला मोर्चाउन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी और पदोन्नति में आरक्षण देने का एकट सन् २००२में बनाया गया था। इसके विरुद्ध सवर्णों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी। इस विषय में प्रदेश सरकार ने उदासीनता बरती और अपना पक्ष दमदारी से नहीं रखा। इसके कारण हाईकोर्ट ने इस एकट को निरस्त कर दिया। यही नहीं इस अवधि में पदोन्नत हुए लोगों को पदावनत करने का भी आदेश दे दिया। सरकार के इस रवैये पर राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में रोष व्याप्त है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बीस मार्च 2018 को दिए गए फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि दलित अत्याचार अधिनियम को इस फैसले से नख दंत विहीन बना दिया गया है। इस फैसले से नाराज दलितों ने दो अप्रैल को भारत बंद का सफल आयोजन किया था। इस दौरान भी प्रदेश सरकार ने उदासीनता बरती जिससे आठ लोगों की जान चली गई थी। इससे भी दलित समाज में असंतोष व्याप्त है। उनके साथ दलित नेता श्री बरैया, सुश्री कंचन दास, सुशील एवं श्री नागले भी उपस्थित थे।

कर्नाटक में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना

बेंगलुरु

जेडीएस की कनार्टक इकाई के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि वह `किंगमेकर' नहीं बनेंगे बल्कि राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें `किंग' के रूप में आशीर्वाद देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जेडीएस अपने बलबूते सत्ता में आएगी। चुनाव प्रचार में लगे कुमारस्वामी लोगों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी पार्टी को मौका देने की अपील कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा, `मुझे जेडीएस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के आने का पूरा भरोसा है। इस संबंध में मुझे रत्तीभर भी संदेह नहीं है।'

अमित शाह विरोधी पार्टियों के नेताओं की खरीद फरोख्त मे माहिर है आप भी अपनी कीमत की गड़ना कर लीजिये और अपने पार्टी के सदस्यों को भी आगाहकर दीजिये कहीं सस्ते मे न बिक जाय

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताया गया है जिसमें जेडीएस किंगमेकर के रूप में उभर सकती है। कर्नाटक की 225 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 मई को चुनाव होंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य 113 सीटों पर जीत हासिल करने का है। उन्होंने कहा,`मैं 113 सीटों का लक्ष्य तय कर रहा हूं। मैंने रणनीतिक रूप से तैयारियां की हैं, जो 113 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए मेरी राय में आखिर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा। लोग मुझे सफल बना देंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है।'

एक सवाल के जवाब में कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी वर्तमान गणना के अनुसार, जेडीएस आराम से 97-105 सीटों तक पहुंच जाएगी और अब शेष सीटों को पाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि आगामी विधानसभा चुनाव जेडीएस के लिए `अस्तित्व की

लड़ाई' है क्योंकि पिछले 10 साल से हम सत्ता से बाहर हैं।' कुमारस्वामी ने कहा,`हम अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में नहीं आना चाहते। पिछले दस वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस ने कई समस्याएं खड़ी की हैं। मैं इन्हें दूर करना चाहता हूं। इसके लिए कर्नाटक को सुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता है।'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस आरोप पर कि जेडीएस बीजेपी की `बी टीम' है, कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी राय में सिद्दरमैया बीजेपी की `बी टीम' हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जेडीएस को बीजेपी की (बी टीम) बताया था। राहुल का कहा था कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को वोट देने का सीधा मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने पलटवार करते हुए कहा था, (जब सिद्धारमैया डेप्युटी सीएम और धरम सिंह सीएम थे तो हम कांग्रेस के लिए टीम बी थे और अब दोबारा हम देखेंगे कि हम कांग्रेस के लिए टीम बी बनते हैं या फिर कांग्रेस जेडीएस के लिए टीम बी बनती है।) गुजरात चुनाव के दौरान भी सियासी हालात बीजेपी के अनुकूल नहीं थे, लेकिन मोदी के चुनाव अभियान में उतरने के बाद माहौल बदला था और पार्टी ने जीत हासिल की थी. पार्टी ने मोदी-शाह की कई रैलियों का प्रोग्राम बनाया है.

योजनाओं को सफल बनाते हैं अफसर बोले शिवराज

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। सिविल सर्विस डे पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस के अफसरों को खासी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एक ओर तो अफसरशाही के कामकाज की भूरी भूरी प्रशंसा की वहीं अफसरशाही पर सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने का आरोप भी मढ़ दिया। सबसे लंबे अंतराल तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री के इस व्यवहार के अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा में मुख्यमंत्री के विरोधियों ने तो मुख्यमंत्री की शासन शैली को ही कटघरे में खड़ा करना शुरु कर दिया है।

नौकरशाहों के बीच आपसी मनमुटाव के बारे में उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में आने के बाद अफसरों में इतना ज्यादा अहम आ जाता है कि वे अपने प्रतिद्वंदी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सिविल सर्विस डे पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने अफसरों के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी संबोधित किया ।उन्होंने अधिकारियों की तारीफ भी की और कई बार तो नाम लेकर उन्हें नसीहत भी दे डाली। इसके लिए उन्होंने कृषि सुधारों के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले अफसर राजेश राजौरा को अपने उदाहरण के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी योग्यता के कारण ये नौकरी मिली है। इसलिए उन्हें सीमित कार्यकाल की इस नौकरी में ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य पूर्ति का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत तड़प के साथ काम करता हूं और कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए काम करते हैं।

मुख्यमंत्री बोले कि अंग्रेजों से पहले भी सिविल सर्विस देश में मौजूद थी। आईसीएस अफसर भी प्रशासन की रीढ़ हुआ करते थे। मध्यप्रदेश में सुशासन को लेकर कई आमूल चूल बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को हमेशा याद किया जाएगा। प्रशासन को जनता के करीब ले जाने में इस सरकार ने जितना काम किया उतना आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अफसरों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। ढीले ढाले अफसरों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे 10 से 5 की नौकरी नहीं करें उन्हें समाज को बदलने और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। कार्यक्रम में लोक सेवा उत्कृष्ठता पुरस्कार के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और पशुपालन विभाग, उत्कृष्ट जिले के लिए देवास और होशंगाबाद को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम करने पर सीहोर के रवीन्द्र बांगरे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव बीपी सिंह, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ सभी सेवाओं के तमाम अफसर उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जनता से निरंतर संवाद करना जरूरी होता है। इसके लिए सभी राजनेता समय समय पर घोषणाएं करते हैं। ये घोषणाएं जनता की जरूरतों का दर्पण होती हैं। उन घोषणाओं पर कैसे अमल करना है। कितना अमल करना है और कब करना है ये तय करना अफसरों का काम होता है। इस सबके दौरान अफसरों पर ही ये जवाबदारी होती है कि वे उन घोषणाओं का मर्म समझें। उनके आधार पर कार्ययोजना तैयार करें। अमल करने के लिए आवश्यक संवाद स्थापित करें और फिर उन योजनाओं को साकार करें। अधिकारी यदि सरकारी नौकरी को पराया काम समझेंगे तो फिर उन योजनाओं की आत्मा निकल जाएगी। उन्हें मिशन के तौर पर काम करना होगा। इसके बाद जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा वे जरूर सफल होंगी।

मुख्यमंत्री ने अफसरों के बीच कहा कि लोग हमेशा कहते थे कि चौबीस घंटों तक पूरे प्रदेश में बिजली देना असंभव है। इसके बावजूद अफसरों ने समन्वय से काम किया और चौबीस घंटों तक बिजली देना संभव हुआ। मध्यप्रदेश में बिजली, सड़क और पानी तीनों मोर्चों पर बेहिसाब काम हुआ। इसके बावजूद अभी कई कमियां रह गईं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के समय अधिकारियों ने कहा था कि ये काम कैसे हो पाएगा लेकिन बाद में अधिकारियों ने ही योजना को अच्छे से बनाकर उसे लागू भी कराया7 उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिविल सर्विस के काम से मैं संतुष्ट हूं। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं।यही कारण है कि मध्यप्रदेश में लगभग सभी मोर्चों पर अच्छे नतीजे आए हैं। हम कई क्षेत्रों में लगातार पुरस्कार जीत रहे हैं। प्रदेश में बदलाव आज नजर आता है तो इसकी एक बड़ी वजह यहां की अफसरशाही भी है।

उन्होंने कहा कि बेटी बोझ नहीं वरदान है, यह कहने से तो होगा नहीं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना बनाई और आज यह मध्यप्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है7 हम यदि इसी तरह तमाम योजनाओं को लागू करेंगे तो नतीजे जरूर मिलेंगे। अचानक आने वाली चुनौतियों से निपटने में अफसरशाही केवल इसलिए ही सफल हो पाती है कि वह चाक चौबंद थी। जहां लापरवाही होती है वहां असफलताओं का लांछन सरकार को भी झेलना पड़ता है। इन्हीं हालात में हमने भावान्तर भुगतान योजना बनाई थी7हमने कोशिश की थी कि सरकार जिस उपज का उपार्जन करे उसमें मिट्टी, कंकड़ और भूसा न आए। हमने छलनी लगाने की कोशिश की। जब हमने अफसरों से चलनी लगाने को कहा तो हमारे राजेश राजौरा जैसे अफसरों ने कुछ इतनी ढील छोड़ दी कि कचरे के साथ साथ चने गेहूं के दाने भी निकल गए। इसके बावजूद हमारी सोच सकारात्मक थी। हम लोगों को लाभ देना चाहते थे। जिसमें हम सफल भी हुए।

सरकार पर अफसरशाही के चंगुल में फंसने के आरोपों पर उन्होंने कहा

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

उत्तर पुस्तिका पाना परीक्षार्थी का अधिकार

विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव को सूचना आयोग की फटकार

भोपाल,(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। म.प्र. राज्य सूचना आयोग ने परीक्षार्थी को उसकी उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने से इंकार करने के विधि विरूध्द कृत्य के लिए विक्रम विश्विद्यालय उज्जैन के कुलपति व कुलसचिव को जमकर फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वे 7 दिन में अपीलार्थी को उसकी उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति निःशुल्क प्रदाय कर 28 अप्रेल तक आयोग के समक्ष सप्रमाण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें । अन्यथा स्थिति में उनके विरूध्द सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) व 20 (2) के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान आकर्षित होंगे ।

अपीलार्थी कु0 तितिक्षा शुक्ला की अपील मंजूर करते हुए राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका परीक्षक की राय का दस्तावेज है जो धारा 2 के तहत 'सूचना' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नागरिकों को लोक प्राधिकारी के नियंत्रण या अधिकार में रखी ऐसी सभी सूचनाओं को पाने का अधिकार है। केन्द्रीय सूचना आयोग व विभिन्न राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित निर्णयों में भी अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के परीक्षार्थी के वैधानिक अधिकार की पुष्टि की जा चुकी हैं । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल बनाम आदित्य बंदोपाध्याय मामले में सुस्पष्ट आदेश पारित किया जा चुका है कि परीक्षार्थी को अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है । उत्तरपुस्तिकाओं में दी गई सूचनाओं के प्रकटन से प्रतिलिप्याधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता है । अतः परीक्षा लेने वाले निकायों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 9 की छूट प्राप्त नहीं होगी ।

सूचना आयुक्त ने विश्वविधालय की इस दलील को विधि विरूध्द करार दिया कि वि0वि0 समन्वय समिति द्वारा मंजूर स्थायी समिति की अनुशंसा अनुसार वि0 वि0 व महाविधालय के विधार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके कारण वैधानिक कठिनाईयां बढ़ने की आशंका है। अतः सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं दी जा सकती है, केवल उसका अवलोकन कराया जा सकता है।

आरटीआई एक्ट सर्वोपरि-इस संबंध में अपीलीय अधिकारी/कुलपति व लोक सूचना अधिकारी/कुलसचिव के निर्णय खारिज करते हुए आयुक्त आत्मदीप ने फैसले में कहा ङ्क अधिनियम की धारा 22 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सर्वोपरि (ओवर राईडिंग) प्रभाव रहेगा । इसका आषय यह है कि यदि अन्य किसी कानून/नियम/प्रावधान में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से विसंगति रखने वाला कोई प्रावधान है तो ऐसा असंगत प्रावधान मान्य नहीं होगा और उसके स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान मान्य होंगे । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि होने से, परीक्षा लेने वाले निकाय इस बात से आबद्ध हैं कि वे अपने नियमों/विनियमों में विपरीत प्रावधान होने के बावजूद, परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण करने दें और चाहे जाने पर उसकी प्रति प्रदान करें ।

अपील संबंधी जानकारी देना जरूरी-अपीलार्थी के सूचना के आवेदन का नियत अवधि में निराकरण न करने, अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय अपील संबंधी जरूरी सूचना न देने तथा प्रथम अपील की सुनवाई में अपीलार्थी के प्रतिनिधि को न सुनने पर भी नाराजगी जताते हुए आयोग ने कुलपति व कुलसचिव को आइंदा ऐसी वैधानिक त्रुटि न करने की चेतावनी दी है ।

यह है मामला- कु0 तितिक्षा शुक्ला ने वि0 वि0 से मेनेजमेंट एकाउंटिंग विषय के प्रश्नपत्र की स्वयं की उत्तर पुस्तिका की प्रति चाही थी जिसे देने से कुलसचिव ने यह कह कर इंकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रति देने का प्रावधान नहीं है । कुलपति ने भी इसी आधार पर प्रथम अपील खारिज कर दी ।

आयोग ने कुलपति व कुलसचिव के आदेशों को निरस्त कर अपीलार्थी को उत्तर पुस्तिका की प्रति देने का आदेश पारित कर दिया ।

भाजपा संगठन को एकजुट करने में सफल होते राकेश सिंह

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। इसी के साथ दोनों प्रमुख पार्टियों में मुकाबले से पहले अंदरूनी उठापटक का दौर भी शुरु हो गया है। लंबे समय से दोनों ही पार्टियों में संगठनात्मक बदलाव की कवायद चल रही है। भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से ही मौजूद है, जबकि नंदकुमार सिंह चौहान की जगह उन्हें सख्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी मिल गए हैं। उनके साथ केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने चुनाव प्रचार अभियान समिति का चुस्त नेटवर्क भी चैतन्य कर दिया है। राकेश सिंह भले ही प्रदेश के मानचित्र पर तुलनात्मक रूप से नए हैं लेकिन उन्हें पार्टी आलाकमान के सुरताल ने ताकतवर बना दिया है। समय से राज्य में पार्टी का सबसे विश्वसनीय चेहरा बने हुये है वे एक तरह से मध्यप्रदेश में भाजपा का पर्याय बन चुके हैं लेकिन 2014 के बाद से पार्टी में शिवराज की पुरानी वाली स्थिति नहीं रह गयी है, इधर लगातर कई उपचुनाव में हुयी हार को सूबे में उनकी ढीली पड़ती पकड़ के रूप में देखा जा रहा है, मुंगावली और कोलारस के उपचुनाव में हार से पहले उसे चित्रकूट और अटेर विधानसभा के उपचुनाव में भी मात मिल चुकी है. जबकि पार्टी की तरफ से इन चुनावों में पूरी ताकत और तमाम तरह के संसाधनों को झोंक दिया गया था. चुनाव के मुहाने पर रव ? मुख्यमंत्री और लगातार अपनी तीसरी पारी पूरी करने जा रही सत्ताधारी पार्टी के लिये ये हारें खतरे की घंटी की तरह हैं जिसके बाद से संगठन में बदलाव की आवाजें मुखर होने लगी थीं और अंत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने विश्वासपात्र अध्यक्ष को बदलने के लिए राजी होना पड़ा।

लेकिन इस बदलाव के लिये राष्ट्रीय नेतृत्व और शिवराजसिंह के बीच लंबी खींचतान चली है, शिवराजसिंह चौहान चाहते थे कि उनके किसी विश्वस्त नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले और इस मामले में उनकी पसंद गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ नरेंद्र सिंह तोमर थे जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा या कैलाश विजयवर्गीय को कमान देना चाहता था. चूंकि यह चुनावी साल है इसलिए दोनों तरफ से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गयी और फिर राकेश सिंह के नाम पर सहमति बनी. इस तरह से मध्यप्रदेश भाजपा के दोनों चौहानों में से एक नंदकुमार सिंह चौहान की विदाई हो गयी लेकिन दुसरे चौहान शिवराज सिंह अपनी जगह पर डटे हुये हैं.इस पूरी परिघटना में राष्ट्रीय नेतृत्व ने सूबे में शिवराज के सियासी रकीबों को निराश किया और शिवराज एक बार फिर यह सन्देश देने में कामयाब हुये है कि अभी भी यह नौबत नहीं आई है कि मध्यप्रदेश भाजपा में कोई भी फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ किया जा सके. महाकौशल से आने वाले राकेश सिंह तीन बार से सांसद रहे हैं, इसके अलावा लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक ,महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी और कईसंसदीय समितियों के सदस्य हैं. वे पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनकी पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में है. उनके भाजपा संगठन से बहुत मजबूत रिश्ते है. हालांकि विपक्षी कांग्रेस उन्हें मजबूरी का सौदा मानती है कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान है कि (भाजपा ने समझौते के तहत राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी है वे इस पद के हिसाब से हल्के हैं.)

राकेश सिंह को भले ही सूबे में पार्टी का कमान मिल गया हो लेकिन इसी के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव अभियान समिति की कमान भी सौंप दी गयी है इस समिति में नरोत्तम मिश्रा , कैलेश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता सदस्य के तौर पर शामिल हैं. भाजपा में चुनाव अभियान समितियों का बड़ा महत्त्व होता है और जाहिर है राकेश सिंह को सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी मिली है चुनाव अभियान की नहीं. इन सबके बीच अध्यक्ष के तौर उन्हें ुद को साबित करने की चुनौती होगी. मुख्यमंत्री के साथ उन्हें चुनाव अभियान समिति से तालमेल बिठाना होगा साथ ही उन्हें इस चुनावी साल में सत्ता विरोधी माहौल और पार्टी के अन्दर गुटबाजी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना होगा. लेकिन असली चुनौती तो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की होगी मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने का असली दायित्व उन्हीं का होगा और उन्हीं के चेहरे और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके परफॉरमेंस से साथ ही भाजपा चुनाव ल ?गी. लेकिन राज्य में इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा है.

बहरहाल इधर लम्बे समय से चली आ रही विपक्षी कांग्रेस में भी असामंजस्यता की स्थिती भी समाप्त हो गयी है पार्टी ने कमलनाथ को सूबे में पार्टी का कमान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया है. इस घोषणा के साथ ही अब लम्बे समय बाद भाजपा को कांग्रेस से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है . कुल मिलाकर शिवराजसिंह चौहान का पार्टी संगठन और सरकार पर नियंत्रण बना हुआ है, भाजपा का मौजूदा शीर्ष नेतृत्व अपने अलावा किसी और को मजबूत शक्ति केंद्र के रूप में देखना पसंद नहीं करता है और ना ही समझौते में रुकीन करता है लेकिन शिवराज उसे समझौते के स्तर पर लाने में कामयाब हुये हैं. राज्य इकाई आज भी उन्हें चुनौती देने की स्थिति में कोई नहीं है।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कमलनाथ और सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस की नयी टीम भाजपा को चौथी बार सत्ता में वापसी से रोकने में किस तरह की रणनीति अपनाती है . फिलहाल पार्टी के अंदर वे चुनौती-विहीन नजर आ रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद अगर भाजपा जीतती है तो पक्के से नहीं कहा जा सकता कि यही स्थिति बनी रहेगी और फिर लगातार सत्ता में रहने अपने खतरे भी तो है जो खुली आँखों से तो नजर नहीं आते हैं लेकिन ऐन मौके पर पासा पलट सकते हैं .

कर्नाटक में भाजपा की रणनीति ने बनाए गुजरात से हालात

कुबूल अहमद

नईदिल्ली,कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी जंग 2019 का सेमीफाइनल मानी जा रही है. कांग्रेस सिद्धारमैया के मजबूत नेतृत्व के चलते आत्मविश्वास से भरी है. वहीं बीजपी के आंतरिक सर्वे ने भी भगवा पार्टी को बड़ी राहत दी है. सर्वे के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है. इससे पहले इंडिया टुडे के सर्वे में भी बीजेपी-कांग्रेस के बीच महज 2 फीसदी वोटों का अंतर सामने आया है. इससे साफ है कि कर्नाटक की राजनीतिक लड़ाई एकतरफा नहीं, बल्कि कांटे की है.

बीजेपी का आंतरिक सर्वे

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने एक पेशेवर एजेंसी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत समझने के लिए सर्वे कराया. पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक राज्य की सियासी लड़ाई एकतरफा नहीं बल्कि बीजेपी-कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है. इससे बीजेपी को राज्य में माहौल अपने पक्ष में बनाने का मौका मिल गया है.

मोदी-शाह से उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के आंतरिक सर्वे के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेताओं के चुनाव प्रचार में उतरने की मांग बढ़ी है. पीएम मोदी ने जिस प्रकार गुजरात चुनाव में आखिरी दौर में उतरकर सियासी माहौल को पार्टी के पक्ष में बनाया था. उसी तर्ज पर कर्नाटक में भी प्रचार करने की

संभावना मानी जा रही है. बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कर्नाटक के चुनाव प्रचार को धार देने की रणनीति बनाई गई.

बीजेपी के सर्वे में किसी को बहुमत नहीं

एक बीजेपी नेता ने कहा, पिछले कुछ महीनों में किए गए सर्वे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जीत मिलती नजर नहीं आ रही है. कुछ सर्वे में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है और कुछ में बीजेपी को. हालांकि पार्टी के आंतरिक सर्वे के परिणाम को साझा नहीं किया गया है. लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कर्नाटक जंग को एकतरफा जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है.

जेडीएस किंग मेकर

उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस की सरकार बन रही है. ऐसे में एचडी देवेगौड़ा की अगुआई वाली जनता दल (एस) किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है. उन्होंने कहा कि अभी भी समय है और हमें उम्मीद है कि हमारे स्टार प्रचारक, पीएम नरेंद्र मोदी के राज्य में एक पूर्ण अभियान शुरू करने के बाद राज्य का माहौल बदलेगा और बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी.

इंडिया टुडे का सर्वे

देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल (आजतक) इंडिया टुडे ,समूह ने कार्वी इनसाइट्स के साथ ओपिनियन पोल किया. इसके मुताबिक कर्नाटक 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी. कांग्रेस को राज्य की कुल 224 सीटों में से 90 से 101 सीटें मिलती दिख रही हैं. बीजेपी को 78 से 86 सीटें और जनता दल (एस) को 34 से 43 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं अन्य को इस बार 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है.

तंबाखू छोड़ना सिखाएगा क्विट लाईन नंबर

भोपाल । सरकार ने तम्बाकू सेवन की लत को छोड़ने वालों के लिए तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विटलाइन नंबर) जारी किया है। सरकार ने कंपनियों को ऐसे लोगों के लिए अब तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर ही क्विट लाइन नंबर लिखने की अधिसूचना जारी की है। नई चेतावनी 1 सितंबर, 2018 से प्रभावी होंगी ।

वायॅस ऑफ टोबेको विक्टिम्स (वीओटीवी) के स्टेट पैट्रन एंव कैंसर सर्जन डा.ललित श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना में कहा है कि तम्बाकू पैकेटों पर 85 प्रतिशत की नई पैक चेतावनी होगी, जिसमें तम्बाकू उपयोग के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, और तम्बाकू सेवन की लत को छोड़ने वालों के लिए तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) लिखना होगा। अधिसूचना के अनुसार अब तम्बाकू के हर उत्पाद के पैकेट पर तम्बाकू से कैंसर होता है और तम्बाकू के कारण दर्दनाक मौत होती है के संदेश के साथ तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) 1800-11-2356 लिखा होगा।

सरकार ने ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे रिपोर्ट 2017 के परिणामों को देखकर तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) को शुरू किया है। इस सर्वे में 62 प्रतिशत सिगरेट धूम्रपान करने वालों, 54प्रतिशत बिड़ी धूम्रपान करने वालों और 46 प्रतिशत धुएं रहित तम्बाकू उत्पादों के उपयोगकर्ताओं ने तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी लेबल देखकर छोड़ने का सोचा था।

सरकार द्वारा तंबाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) जारी होने की अधिसूचना पर पेशे से वकील 68 वर्षीय उमेश नारायण ने कहा कि तम्बाकू पैकेटों पर तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) यदि यह पहले पेश किया गया होता तो इससे उन्हें तम्बाकू छोड़ने में मदद मिलती। वे तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दे रहे थे। वे ओरल कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, बहुत से लोग तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी आलस की वजह से इंटरनेट पर तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) का पता लगाने या जानकारी की कमी या दूसरों से पूछने में शर्म महसूस करने और अन्य कारणों से, उनकी तंबाकू का उपभोग करने की आदत बनी रहेती है और वे कैंसर और अन्य घातक रोगों के शिकार होकर अपना जीवन खत्म कर लेते हैं।

टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉ.पंकज चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण हर साल करीब 12 लाख मौतें होती हैं।

उन्होंने कहा कि हर बार, यदि कोई व्यक्ति तम्बाकू उत्पाद खरीदता है तो उसे स्वास्थ्य पर तम्बाकू के उपयोग के प्रभाव को दिखाए जाने वाले चित्रों को देखेगा, जो निश्चित रूप से उसे तम्बाकू उपभोक्ता को छोड़ने के लिए मजबूर करेगी और अब पैकेट पर तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) उपभोक्ता को निश्चित रूप से नंबर पर कॉल करने और तंबाकू की लत छोड़ने के तरीके ढूंढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉ.पंकज चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण हर साल करीब 12 लाख मौतें होती हैं। गैर-प्रसारी रोग (एनसीडी) का लगभग 40: कैंसर, ह्रदय-नाड़ी रोगों और फेफड़ों के विकारों सहित सीधे तौर पर तम्बाकू के उपयोग के कारण होते हैं। भारत में लगभग 50 प्रतिशत कैंसर तंबाकू से होताहै और 9 प्रतिशत मौखिक कैंसर के रोगी इलाज के 12 महीने के भीतर मर जाते हैं। डॉ.पंकज चतुर्वेदी उस समिति का के भी सदस्य है, जिसने तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर चेतावनी लिखने को अंतिम रूप दिया है।

तम्बाकू पैकेजों पर ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी तंबाकू के उपयोग के गंभीर और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है, खासकर युवाओं, बच्चों और अनपढ़ व्यक्तियों के बीच। इसे साबित करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्रभावी चेतावनी लेबल तंबाकू के उपयोग से संबंधित खतरों के बारे में जानकारी को बताते हैं और किशोरावस्था में तंबाकू का उपयोग करने के लिए इरादों को कम कर सकते हैं, तम्बाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ने के लिए राजी कर सकते हैं और पूर्व उपयोगकर्ताओं को फिर से शुरू करने से रोक सकते हैं।

संबध हैल्थ फांउडेशन (एसएचएफ) के ट्रस्टी संजय सेठ ने कहा कि इस अधिसूचना जारी होने के बाद महत्वपूर्ण यह है कि तंबाकू उत्पादो के पैकेटों पर तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) (1800112356) की छपाई उपयोगकर्ताओं को तम्बाकू छोड़ने में सहायता करेगा। नए चेतावनियों के परीक्षण के दौरान परीक्षण के दौरान उपयोगकर्ताओं के लक्षित समूहों (धूम्रपान और धुआं रहित दोनों) और गैर-उपयोगकर्ता और फोकस रूप के प्रतिभागियों के बीच डमी पैक के साथ परीक्षण के लिए फील्ड परीक्षण किया गया था। तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) (1800112356) तम्बाकू उत्पादों के पैक पर लिखना एक नया विचार है जो धूम्रपान करने वालों को तम्बाकू छोड़ने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वे इस बात को मानते हैं कि धूम्रपान करने वाले उपभोक्ता इसे लत से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सहायता कहाँ और कैसे प्राप्त करें। ऐसे लोगों के लिए, तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) बहुत उपयोगी होगी।

कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि पेशेवर सलाहकार बहुत महंगे हैं और जो लोग इनकी फीस वहन नहीं कर सकते, अब तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) पर कॉल

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

श्री जी ट्रेडर्स

ईशान इंद्र भवन इंद्रपुरी भोपाल

प्रोपाईटर- एस.के जैन

बढ़ती गर्मी में घमौरियां करें हलाकान

इससे पहले कूलर घर ले आएं श्रीमान

उत्तम गुणवत्ता के कूलर एवं फिटिंग्स मिलने का सबसे भरोसेमंद प्रतिष्ठान

आज ही बुकिंग कराएं -8982435370

योजनाओं को सफल बनाते हैं अफसर बोले शिवराज

(पढ़िए पेज चार का शेष भाग)

कि अधिकारियों और नेताओं के बीच समन्वय में भारी कमी होती है। इसकी वजह से कई बार टकराव के हालात बन जाते हैं। जनता से सीधे संपर्क में रहने के कारण जन प्रतिनिधि जमीनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। लोग उन्हें अपनी शिकायतें सुनाते हैं। काम न होने के कारण गालियां भी देते हैं। बार बार उलाहने मिलने के कारण नेतागण तनाव में होते हैं। यदि अफसर उनके साथ तालमेल बनाए रखेंगे तो फिर ये टकराव नहीं होगा। काम न हों तो सरकार को दोषी माना जाता है अफसर तो ये कहकर बच लेते हैं कि आपने सरकार बनाई है आप ही इनसे काम कराईए।जबकि एक दूसरे के खिलाफ जनता को भड़काकर न तो जनता का लाभ किया जा सकता है और न ही सरकार का। यदि हमें जनता को बेहतर माहौल देना है तो जनप्रतिनिधियों, अफसरों और जनता सभी के बीच में तालमेल बिठाना होगा।

कार्यशाला में विशेष विशेषज्ञों द्वारा योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री राजीव शर्मा ने प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, एआईजी श्री सुदीप गोयलकर ने साइबर क्राईम एवं जागरूकता, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने, Compaign Against Untouchablity – An Intresting E&periment, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन डॉ. पीसी दुबे ने वनों की वृद्धि प्रदेश की समृद्धि, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री विश्वनाथन ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बी. चंद्रशेखरन ने प्रदेश के कार्यालय में ई-ऑफिस का संचालन एवं विभागीय पोर्टल पर चैटबॉट का क्रियान्वयन और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आलोक कुमार ने ऑल इण्डिया टाईगर एस्टीमेशन-2018 पर प्रस्तुतीकरण दिया।

कार्यशाला में अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला भी मौजूद थे। अपर सचिव के.के. कतिया ने आभार प्रदर्शन किया।

जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा

नई दिल्ली(पीआईसी)। राजस्व के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया है। उनका कहना है कि यह आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का सबूत है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2018 में जीएसटी संग्रह 1,03,458 करोड़ रुपये रहा जो किसी भी महीने में अब तक का सर्वाधिक है। अप्रैल में सीजीएसटी संग्रह 18,652 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,704 करोड़ रुपये, क्षतिपूर्ति सैस 8,554 करोड़ रुपये और आइजीएसटी 50,548 करोड़ रुपये आया। आइजीएसटी के रूप में जुटायी गयी 50,548 करोड़ रुपये की राशि में 21,246 करोड़ रुपये आयात पर आइजीएसटी के भी शामिल हैं। इसी तरह सैस की 8,554 करोड़ रुपये की राशि में से 702 करोड़ रुपये की राशि आयातित उत्पादों पर सैस के रूप में जुटाई गयी।

इस साल मार्च में जीएसटी संग्रह 89,264 करोड़ रुपये था। एक जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी से सरकारी खजाने में 7.41 लाख करोड़ रुपये राजस्व आया।

सरकार का कहना है कि जीएसटी संग्रह में सुधार की वजह बेहतर अनुपालन और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना है। हालांकि लोग वित्त वर्ष के अंत में पिछले महीनों का बकाया कर भी जमा करते हैं, इसलिए अप्रैल 2018 के जीएसटी संग्रह के आंकड़ों को भविष्य के ट्रेंड के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

मंत्रालय के अनुसार आइजीएसटी के सेटलमेंट के जरिए अप्रैल में केंद्र को सीजीएसटी के रूप में 32,493 करोड़ रुपये और राज्यों को एसजीएसटी के रूप में 40,257 करोड़ रुपये मिले हैं।

जहां तक रिटर्न दाखिल होने की बात है तो मार्च महीने के लिए 30 अप्रैल तक 69.5 प्रतिशत व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी दाखिल किया है। मार्च में 87.12 लाख कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करना था जिसमें से 60.47 लाख ने रिटर्न भरा। वहीं जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 19.31 लाख कंपोजीशन डीलरों को रिटर्न दाखिल करना था जिसमें से 11.47 लाख ने तिमाही रिटर्न दाखिल किया है और 579 करोड़ रुपये टैक्स जमा किया है जो में आए 1.03 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी के आंकड़े में शामिल है।

जीएसटी के ताजा आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेटली ने कहा कि आर्थिक माहौल बेहतर होने, ई-वे बिल के क्रियान्वयन और जीएसटी अनुपालन बेहतर होने से जीएसटी संग्रह में यह सकारात्मक ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। जेटली ने इस उपलब्धि के लिए सभी करदाताओं, जीएसटी काउंसिल के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को बधाई भी दी है।

कश्मीर पर दो टूक फैसला लेना होगा:बख्शी

(पढ़िए पेज एक का शेष भाग)

देश को कमजोर करने की कोशिशें चलती रहती हैं। भारत सरकार को इस अराजकता को रोकना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अतुलनीय रहा है। इसके बावजूद पिछली सरकारों ने दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर उनकी मूर्तियां नहीं लगाई । देश को बताया गया कि आजादी केवल गांधीजी के प्रयासों से आई जबकि ये सच्चाई नहीं है। आजाद हिंद फौज यदि ब्रिटिश हुकूमत को खुला चैलेंज नहीं देती तो अंग्रेज यहां से नहीं भागते। इसीलिए हम देश में पैन इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। हम देश से आव्हान करते हैं कि आजाद हिंद फौज के गठन के दिन इस बार हम दिल्ली चलो के नारे के साथ राम लीला मैदान में एकत्रित हों। सरकार से मांग करें कि वो जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट लागू करे। उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं पर अब तक के कार्यकाल में सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास नहीं किया है। बेशक सरकार के सामने देश को संवारने की काफी सारी चुनौतियां हैं पर देश को कारगर बनाने के लिए हमें कई मूलभूत फैसले लेने होंगे जिससे मौजूदा व्यवस्था को बदला जा सके।

दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक राजशेखर व्यास ने कहा कि देश को मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए मैंने स्वयं 29 ग्रंथ लिखे हैं ताकि देश की नई पीढ़ी इस विशाल देश का पथ सुनिश्चित कर सके। आजादी के बाद के बरसों में हमें गुलामी की भाषा ही सिखाई जाती रही है। पांच सौ साल मुगलों और दो सौ साल अंग्रेजों की गुलामी से पहले का गौरवशाली इतिहास हमें नहीं बताया गया है। विदेशों से पढ़कर आने वाले भारत के नेताओं का भारतीयता से परिचित न होना इसकी सबसे बड़ी वजह थी। उज्जैन के ही पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास ने इसीलिए 1928 से उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह मनाना शुरू किया था।भारत के नेतागण शेक्सपियर की बात तो करते थे लेकिन वे कालिदास को नहीं जानते थे। जबकि तुलनात्मक रूप से महाकवि कालिदास की रचनाएं ऊंचे दर्जे की रहीं हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का दूरदर्शन आज भी देश से गहरा जुड़ाव रखता है। मीडिया के इस मंच की विराटता का अहसास आमतौर पर लोग नहीं लगा पाते हैं जबकि इसके विभिन्न चैनल समाज के हर तबके से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आकाशवाणी कभी चाटे का सौदा बना दी गई थी वो अब अपने पैरों पर खडी है। सरकारी मीडिया को निगम बनाने के बाद इस पर सरकार का भोंपू होने के आरोप तो नहीं लगते हैं लेकिन अभी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने की बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं। ऊर्जावान लोगों को इससे जोड़कर इस माध्यम का पूरा उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कंप्यूटर वैज्ञानिक चंद्रकांत राजू ने कहा कि भारत में उपनिवेशीकरण की मानसिकता ने विश्वविद्यालयों को अपने चंगुल में फंसा रखा है। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं केवल नौकरी खोजते रहते हैं जबकि वे दुनिया के अन्य देशों में जाकर चमत्कृत करने वाले काम करते हैं। अनुसंधान और पेटेंट के मामले में भारत इसलिए पिछड़ा है कि यहां की पढ़ाई विद्यार्थियों को पिछलग्गू बना देती है। बच्चों को गणित समझ नहीं आती फिर भी इस विषय पर आम चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर देश में खुला संवाद होना चाहिए। हमें वास्तविक शिक्षा की दिशा में बहुत प्रयास करने होंगे।

श्री राजू ने कहा कि देश को उपनिवेशीकरण की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव करने होंगे। कंप्यूटर जैसे विषय को बोधगम्य बनाने के लिए हमें अपनी पारंपरिक सोच पर अमल करना होगा। कंप्यूटर गणनाओं का सरल हल प्रस्तुत करता है। यदि हम गणनाओं की शैली नहीं बदलेंगे तो कंप्यूटर के चमत्कारों से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा पर सार्वजनिक बहस जरूरी है।

पत्रकार वार्ता का संचालन मध्यप्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डाक्टर नवीन जोशी ने किया। आभार प्रदर्शन क्लब के महासचिव नितिन वर्मा ने किया। अथितियों का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई, प्रसन्ना शहाणे, ब्रजेश द्विवेदी,अरविंद पटेल, अनुवेद नगाइच ने किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के अलावा मीडिया के प्रतिनिधि गण भी उपस्थित थे।

तंबाखू छोड़ना सिखाएगा क्विट लाईन नंबर

(पढ़िए पेज छहका शेष भाग)

करके सेवा का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए एक और पहलू कि तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) से मदद मांगने से फोन करने वाले का नाम अज्ञात रखने की भावना की भी रक्षा होती है। प्रतिभागियों ने बताया कि अगर कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) को फोन करेगा और तम्बाकू छोड़ने के बारे में परामर्श लेगा, तो वह साथियों, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ सकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगा। इससे भी अन्य लोग तम्बाकू सेवन को छोड़ने के लिए तम्बाकू छोड़ो नंबर (क्विट लाइन नंबर) पर कॉल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 15 अक्टूबर 2014 को केन्द्र सरकार ने सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित किया, जिसमें सभी तम्बाकू उत्पाद पैकेजों के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र (सामने और पीठे) के 85 प्रतिशत को कवर किया गया था। संसद समितियों और तम्बाकू कंपनियों की सिफारिशों और कई उच्च न्यायालयों में पहले से इन चेतावनियों को चुनौती देने के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अंतत: 85 प्रतिशत चेतावनियों का क्रियान्वयन हो पाया।

सिगरेट, बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर दोनों तरफ की मौजूदा सचित्र चेतावनी छापने की अधिसूचना अप्रैल 2016 से राजस्थान उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय निर्देशो पर लागू किया गया था और यह लगभग दो साल से प्रभावी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई, 2016 को तम्बाकू पैक पर 85 प्रतिशत चेतावनियों के कार्यान्वयन के निर्देश देते हुए 85 प्रतिशत पैक चेतावनियों को चुनौती देने के सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15.12.2017 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014 को रद्द कर दिया और वर्ष 2008 की स्वास्थ्य चेतावनी को बहाल कर दिया। इसमें पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र की तरफ 40 प्रतिशत पर चेतावनी की छपाई आवश्यकता है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को केन्द्र सरकार और सिविल सोसाइटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद 8 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर रोक लगा दी।

डालमिया चमकाएगा लालकिला

(पढ़िए पेज एक का शेष भाग)

बहादुर शाह जफर तक के सीन हैं।

किले के पिछले भाग में चल रहे मुमताज महल संग्रहालय को बंद किया जा चुका है। मुमताज महल स्मारक के लिए बी-4 इमारत को तैयार किया जा रहा है। इसे उस इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस समय किले के अंदर केवल एक ही संग्रहालय जनता के लिए उपलब्ध है। यह नौबतखाना के ऊपर चल रहा इंडियन वार मेमोरियल संग्रहालय है। इसे भी आने वाले दिनों में अंग्रेजों के जमाने की इमारत बी-एक में स्थानांतरित किया जाएगा।

लालकिले में चल रही कैंटीन भी बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जो कंपनी इसे चला रही थी। उसका टेंडर समाप्त हो गया था। अब इसे डालमिया समूह नए तरीके से खोलेगा। इसमें कुछ समय लग सकता है।

भारत के संविधान निर्माता

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

की 127वीं जयंती 14 अप्रैल 2018 के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ

बाबा साहब की जन्मभूमि डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर में अम्बेडकर जयंती समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति

श्री राम नाथ कोविन्द

ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

D18016

आकल्पना : म.प्र. माध्यम/2018

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई *फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल.* ***aloksinghai67@gmail.com*** *सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।*